future with the assistance of private sector;

(b) if so, the number of private parties approached and terms and location thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) The Pillaiperumal Nallur Combined Cycle Gas Turbine Power Project of 300 MW capacity is being developed by M/s Dyna Makowski Power Company, Madras — utilising the gas available in Cauvery Basin. The Power Purchase Agreement has already been initiated. CEA has cleared this project in principle and fuel linkage for the project has been obtained from Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India.

Government of Tamil Nadu has informed that a MOU has been signed for development of 2000 MW Gas based power project at Vembar with M/s CRSS Capital Corporation of Houston, USA and M/s Intech Global Resources Inc., USA and another MOU has been signed for development of 1000 MW Gas based power project at Gummidipoondi with M/s GVK Enterprises, Hyderabad.

TNEB has proposed to establish an additional 5 MW Gas Diesel Engine Unit at Narimanam under State Sector utilising the surplus gas.

महेश्वर पन बिजली परियोजना

320. **श्री अजीत जोगी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थापित की जाने वाली महेश्वर पन बिजली परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि संसाधनों की कमी और राज्य में बिजली की मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश की प्रोत्साहित करने की भारत सरकार की नीति के अनुरूप, उन्होंने निजी क्षेत्र में महेश्वर एच.ई.पी. (400 मे.वा.) के क्रियान्वयन का कार्य मैसर्स एस. कुमार्स को सौंपा है ।

Investment by US Companies in the Power Sector

321· SHRI G· Y· KRISHNAN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the outcome of the talks held with the visiting US Energy Secretary, particularly on the issue of counter-guarantees by India;

(b) what are the prospects for investment by the US companies in the power Sector in India and the additional power generation capacity likely to be generated;

(c) whether there had been US pressure on Government to expedite the processing of counter-guarantee terms for seven power projects mooted by US Companies; and

(d) if so, what alternatives are being worked out to replace the counter-guarantee stimulation particularly ensuring punctual payment by the State Electricity Boards through an Escrow A/c.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) During the recent visit of the

US Secretary of Energy Ms. Hazel O' Leary in February 1995, it was agreed that the US Government would provide support in developing the alternatives to counter guarantee further based on the experience in other countries and a workshop could be organised in which US financial institutions, US Department of Energy, USAID and US project developers could participate.

(b) The prospects for investment by the US companies in the Indian power sector are bright which may be seen from the response received from US based companies (including NRIs and Joint Ventures). 23 private power proposals for a capacity addition of 12869 MW involving investment by US companies are at an active stage.

(c) No, Sir.

(d) The Government is working on alternatives to Government of India counter guarantee such as direct supply of power by Independent power Producers (IPPs) to HT consumers, opening of an escrow account for which identified payment by consumers are credited and the payment liability to the IPP is a first charge on this account, linking power generation with distribution, PPA with Power grid Corporation, World Bank guarantee and other alternatives.

विद्युत उत्पादन पर विदेशी कम्पनियों को दी जाने वाली प्रति गारंटी का प्रभाव

322. **श्री रामजेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण में अमरीकी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फाइनैंसियल काउन्टर गारन्टी सिस्टम अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तहत अभी तक कुल कितनी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रणाली को अपनाने के कारण देश में विद्युत उत्पादन तथा परियोजना निर्माण की लागत में भारी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या यह सच है कि सरकार ने भविष्य में इस प्रणाली को न अपनाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) निजी विद्युत नीति के प्रति सम्भावित निवेशकर्ताओं में विश्वास जागृत करने के लिए विदेशी निवेश की दृष्टि से प्रारम्भ में स्वीकृत 8 निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों के भुगतानों की राज्य विद्युत बोर्डों के लिए राज्य सरकारों की गारन्टी को भारत सरकार की प्रति गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया था । आठ परियोजनाओं में से दो के लिए प्रति-गारन्टी सम्बन्धी हस्ताक्षर पहले ही किए जा चुके हैं ।

(ग) जी, नहीं । दूसरी ओर प्रति-गारन्टी से परियोजना ऋण पर ब्याज की दर कम होने से परियोजना लागत कम होगी और इसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन की लागत कम होगी ।

(घ) चूंकि भारत सरकार की प्रति-गारन्टी को एक अस्थायी उपाय के रूप